

384

प्रेषक,

विनोद फोनिया,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत मदों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9013/सू.एवं.लो.स.वि.(लेखा)/बजट आवंटन-प्लान/2014-15, दिनांक 15 मई, 2014 तथा शासनादेश संख्या-318/XXXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 तथा शासनादेश संख्या-80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014-15 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 में विहित व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि ₹ 2178.00 हजार (रुपये इक्कीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है, कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृति नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हैं, की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति करालें।

4- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

5- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

6- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7- निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए।

8- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-14 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2220-सूचना तथा प्रचार के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत संलग्न विवरणानुसार इंगित लेखाशीर्षकों/मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

12- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-318/XXXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 तथा शासनादेश संख्या-80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014-15 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 में निहित प्राविधानों के तहत जारी किये जा रहे हैं तथा उक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित भी किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)  
सचिव।

संख्या-4SS(1)/XXII/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- वित्त अनुभाग-5
- 7- एन0आई0सी0, देहरादून, सचिवालय।
- 8- प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

*Raman*  
(रविनाथ रामन)  
अपर सचिव।